

सिविल प्रकीर्ण

न्यायमूर्ति तेक चंद के समक्ष

राम सिंघ और अन्य, — *याचिकाकर्ता*

बनाम

मुख्य आयुक्त (मुख्य प्रशासक), केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य, — *उत्तरदाता*

C.W.P. सं. 1400 सन् 1967

अक्टूबर 30, 1967

मोटर वाहन अधिनियम (1939 का IV) — धा. 76 — टैक्सियों के लिए पार्किंग स्थानों या स्टैंडों की स्थापना — व्यक्तियों द्वारा स्थान का टैक्सी-स्टैंड की तरह प्रयोग— यदि उस स्थान को टैक्सी स्टैंड के रूप में उपयोग करने की अनुमति दिए जाने के विरुद्ध कारण बताने के लिए किसी नोटिस के हकदार हैं — मोटर वाहन नियमों (1939) — नियमों 7.12(2), 7.13 और 7.22(1) — "परमिट" — का अर्थ — यदि उपमति का पर्यायवाची है — "कब्जाकर्ता" — का अर्थ — यदि क़ानून द्वारा उनमें कोई अधिकार निहित है।

अभिनिर्णित, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 76 संबंधित प्राधिकारी को पार्किंग स्थल निर्धारित करने में सक्षम या सशक्त बनाती है। यह इस अर्थ में वैधानिक दायित्व नहीं है कि विधानमंडल प्राधिकरण को पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने का आदेश देता है और ऐसा नहीं करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाता है। मोटर वाहन अधिनियम के नियम 7.22 में स्टैंड स्थापना के आदेश निरस्त करने का प्रावधान है। एक जिला मजिस्ट्रेट किसी भी समय किसी भी स्टैंड की स्थापना की अनुमति देने वाले किसी भी आदेश को रद्द कर सकता है यदि उसकी राय में किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया हो, आदि। जिला मजिस्ट्रेट का याचिकाकर्ताओं के तंबू हटाने या शहर में कुछ स्थानों को टैक्सी स्टैंड के रूप में अधिसूचित करने और वर्तमान स्थान को टैक्सी स्टैंड के रूप में शामिल न करने का आदेश प्रशासनिक है और कार्यकारी चरित्र का हिस्सा है। वर्तमान स्टैंड का स्थान सार्वजनिक सड़क का एक हिस्सा है और याचिकाकर्ता न तो मालिक हैं, न पट्टेदार और न ही लाइसेंसधारी, वे सिर्फ अतिक्रमणकर्ता थे; और इस प्रकार, वे उस स्थान को टैक्सी स्टैंड के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दिए जाने के विरुद्ध कारण बताने के लिए किसी नोटिस या अवसर के हकदार नहीं हैं।

अभिनिर्णित, "परमिट" शब्द का प्रयोग आम तौर पर दो अर्थों में किया जाता है। इसका मतलब हो सकता है कि एक देना निष्क्रिय सहमति या बस, बाधा नहीं, परमिट का उपयोग कुछ संदर्भों में "इस्तीफा देना", "पीड़ित होना", "सहन करना" और "प्रतिबंध न

लगाना" के रूप में किया गया है। मुझे नहीं लगता कि मोटर वाहन अधिनियम के नियम 7.12 (2) में प्रयुक्त "अनुमति", नियम 7.13 में "अनुमति", और नियम 7.22(1) में "अनुमति" शब्दों को उपरोक्त अर्थ में केवल आपत्ति करने में विफलता या सहमति का एक पर्याय के रूप में समझा जा सकता है। 'परमिट' शब्द काफी लचीलेपन का शब्द है और इसका उपयोग केवल निष्क्रियता या निवारक कार्रवाई से परहेज के संकेतक के रूप में किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस शब्द का उपयोग यहां उस अर्थ में किया गया है। संदर्भ में 'परमिट' को औपचारिक सहमति, अनुदान या प्राधिकरण या स्पष्ट यूसेंस देने का संकेत माना जाना चाहिए।

अभिनिर्णित, "कब्जाकर्ता" वह व्यक्ति है जो बिना किसी वास्तविक दावे या स्वामित्व के रंग के और मालिक की सहमति के बिना, घेरी हुई या बिना घेरी गई भूमि पर बसता है या बसता है। ऐसा व्यक्ति महज एक घुसपैठिया है; और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वहां कितने समय तक बना रह सकता है, कानून में उसका कोई अधिकार नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण, परमादेश या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादियों के विरुद्ध जारी किया जाए जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को टैक्सी-स्टैंड (बस अड्डे, सेक्टर 17 के बाहर) से बाहर निकाला जा रहा है और प्रतिवादियों को कानून के अनुसार कार्य करने का आदेश दिया जाए और साथ ही प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को टैक्सी-स्टैंड से जबरन हटाने से रोका जाए।

कुलदीप सिंघ, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए।

गोपाल सिंघ, महाधिवक्ता (पं.), उत्तरदाताओं के लिए।

आदेश

न्यायमूर्ति तेक चंद - यह संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उन तीस याचिकाकर्ताओं की ओर से उचित रिट जारी करने के लिए एक याचिका है जो चंडीगढ़ में टैक्सियों के मालिक और ड्राइवर हैं। 1957 में, जब बस स्टॉप को बजवाड़ा से सेक्टर 17 में स्थानांतरित किया गया, तो उन्होंने बस स्टैंड में बसों के प्रवेश द्वार के बाहर के क्षेत्र को टैक्सी स्टैंड के रूप में भी इस्तेमाल किया। उनका दावा है कि वे दस साल से अधिक समय से इसका उपयोग कर रहे हैं और वहां लगभग 80 टैक्सियाँ तैनात हैं। यह क्षेत्र सार्वजनिक सड़क के किनारे है। परिसर में तंबू में चार टेलीफोन लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इस जगह को टैक्सी स्टैंड के रूप में इस्तेमाल करने पर अधिकारियों ने कभी आपत्ति नहीं जताई। उन्हें कोई नोटिस जारी किए बिना, कई पुलिसकर्मियों ने

17 जुलाई, 1987 को टैक्सी स्टैंड पर छापा मारा और टेंटों को ध्वस्त कर दिया और टेलीफोन के तार काट दिए और उन्हें तीन दिनों के भीतर अपने बूथ हटाने के लिए कहा गया, अन्यथा उन्हें जबरन हटा दिया जाएगा। और उनकी टैक्सियाँ जब्त कर ली गईं। याचिकाकर्ताओं को बांधने के लिए कोई लिखित आदेश नहीं दिखाया गया।

याचिकाकर्ताओं ने तब कहा कि 2 जून, 1867 को केंद्र शासित प्रदेश के उपायुक्त (प्रतिवादी संख्या 2) ने मोटर अधिनियम की धारा 76 के प्रावधानों के तहत शहर में टैक्सी स्टैंड के रूप में उपयोग के लिए कई स्थान निर्धारित किए थे। वाहन अधिनियम, 1939. स्थान निर्धारित करने के अलावा अभी तक कोई सुख-सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयीं। यह कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को टैक्सी स्टैंड से बाहर करने का आदेश नियम विरुद्ध और असंवैधानिक था और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता था, ऐसा आचरण भी इसके विपरीत था। आम जनता के हितों और याचिकाकर्ताओं को अपना रुख हटाने के लिए कोई उचित नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने उत्तरदाताओं के उस आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरी प्रकृति की रिट जारी करने के लिए कहा था जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को टैक्सी स्टैंड के बाहर से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने प्रतिवादियों को कानून के अनुसार कार्य करने और याचिकाकर्ताओं को टैक्सी स्टैंड से जबरन हटाने से रोकने के लिए परमादेश की प्रकृति की एक रिट जारी करने के लिए भी कहा।

रिटर्न उपायुक्त, चंडीगढ़ द्वारा एक शपथ पत्र के रूप में है। यह दर्शाया गया कि विचाराधीन टैक्सी स्टैंड अनधिकृत था। सेक्टर 17 में बस स्टैंड के अंदर एक के अलावा शहर में अधिकृत टैड स्टैंड थे। जिस स्थान को याचिकाकर्ताओं ने टैक्सी स्टैंड के रूप में इस्तेमाल किया था वह वास्तव में सार्वजनिक सड़क पर स्थित था और इसे टैक्सी स्टैंड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से यह कहा गया कि 14 अप्रैल 1966 को, पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 173 के तहत अनधिकृत टैक्सी स्टैंड से परिचालन करने वाले व्यक्तियों को एक नोटिस (अनुलग्नक आर/एल के माध्यम से) जारी किया गया था। चूंकि उन्होंने इसका अनुपालन नहीं किया था, इसलिए उन्हें सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण खाली करने के लिए कहा गया था। समझाने का कोई असर न होने पर 31 मार्च, 1967 को अनाधिकृत टैक्सी स्टैण्ड हटा दिया गया।

इसके बाद, याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 1, मुख्य आयुक्त से मिले जिन्होंने उन्हें उपायुक्त टैक्सी स्टैंड बनने तक अस्थायी रूप से अपने वर्तमान स्थान पर काम करने की अनुमति दी। छह अधिकारियों और टैक्सी मालिकों के चार प्रतिनिधियों की एक समिति ने अपनी सिफारिशें करने के लिए शहर में बड स्टैंड के लिए साइटों की समीक्षा करने के लिए गठन किया। इस बीच, टैक्सी ऑपरेटरों को उन साइटों पर अपना व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी गई जहां से वे परिचालन

कर रहे थे (अनुलग्नक आर/2 दिनांक 1-4-1967 के अनुसार)। तब यह कहा गया था कि मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 76 के तहत कई स्थानों को टॉ स्टैंड के रूप में निर्धारित किया गया था और 21 जून 1967 को एक अधिसूचना (अनुलग्नक आर/3) जारी की गई थी।

किसी भी रिट के अनुदान का विरोध कई आधारों पर किया गया था कि याचिकाकर्ताओं के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया था और उन्हें टैक्सी ऑपरेटर के रूप में अपना पेशा अपनाने से रोका गया था। उन्हें वैकल्पिक अधिकृत टैक्सी स्टैंड की पेशकश की गई जहां से वे काम कर सकें। अंततः यह कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था जिसके बारे में कहा जा सके कि इसका उल्लंघन किया गया है।

शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 173, जिस पर उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया गया था, की कोई प्रयोज्यता नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि चंडीगढ़ में कोई नगर पालिका समिति नहीं है, धारा के अन्य प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यह धारा सार्वजनिक सड़क पर कब्जा करने की अनुमति देने और रुकावट हटाने की शक्ति को संदर्भित करती है। नगरपालिका समिति के पास कुछ शर्तों पर अनुमति देने की शक्ति है और किसी भी सार्वजनिक सड़क के जमीनी स्तर पर किसी भी चल अतिक्रमण के संबंध में अनुमति वापस लेने या बाड़ के लिए भुगतान या अन्य सामग्री लेने या बदलने का विवेक भी है। किसी भी सार्वजनिक सड़क पर खंभे लगाना, या बिक्री के लिए निर्माण सामग्री या सामान जमा करना या किसी सड़क के अंदर या नीचे खुदाई करना या किसी सार्वजनिक सड़क पर कोई बाड़, चौकी, स्टाल या मचान खड़ा करना या स्थापित करना। उप-धारा (2) में प्रावधान है कि समिति की लिखित अनुमति के बिना उप-धारा (1) द्वारा निषिद्ध किसी भी कार्य को करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन मालिक को हटाने का उचित अवसर देने के बाद ऐसा किया जाना चाहिए। उसकी सामग्री और हटाने में विफलता के मामले में, सामग्री को पुलिस द्वारा हटवाया जा सकता है। जिन नोटिसों के बारे में दावा किया गया था कि उन्हें पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 173 के तहत चार व्यक्तियों को भेजा गया है, उनका कोई फायदा या महत्व नहीं है। इस मामले में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या मोटर वाहन अधिनियम या मोटर वाहन नियमों में निहित किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया गया है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वक अधिवक्ता ने मेरा ध्यान मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 76 और पंजाब मोटर वाहन नियमों की ओर आकर्षित किया है।

धारा 76 में प्रावधान है कि राज्य सरकार या इस प्रकार अधिकृत कोई प्राधिकारी स्थानीय प्राधिकारी के परामर्श से उन पार्किंग स्थानों का निर्धारण कर सकता है जिन पर मोटर वाहन खड़े हो सकते हैं। यह पार्किंग स्थानों के निर्धारण को अधिकृत करने वाला एक सक्षम प्रावधान है। पंजाब मोटर वाहन नियम 7.7 के अनुसार, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन जिला

मजिस्ट्रेट धारा 76 के तहत पार्किंग स्थानों की नियुक्ति के आदेश देने के लिए अधिकृत हैं।

नियम 7.12(2) में प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट, स्थानीय प्राधिकारी के परामर्श से, "किसी भी स्थान को स्टैंड के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक आदेश दे सकता है, और ऐसे आदेश के बिना, कोई भी स्थान स्टैंड के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा।"

नियम 7.13 के तहत, किसी स्थान को स्टैंड के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लेने में, जिला मजिस्ट्रेट को जनता के हितों, स्थल की उपयुक्तता, बचाव से संबंधित कुछ मामलों को ध्यान में रखना होगा। आस-पड़ोस को परेशान करना, आदि।

नियम 7.22 में स्टैंड स्थापना के आदेश निरस्त करने का प्रावधान है। एक जिला मजिस्ट्रेट किसी भी समय किसी भी स्टैंड की स्थापना की अनुमति देने वाले किसी भी आदेश को रद्द कर सकता है यदि उसकी राय में किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया हो, आदि। याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले यह आग्रह किया गया था कि यह अधिकारियों का वैधानिक दायित्व है। टैक्सी मालिकों को स्टैंड प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 76 उपर्युक्त नियमों के साथ पढ़ी जाती है। उपयुक्त अनुभाग और नियमों की भाषा इस तरह के निष्कर्ष की गारंटी नहीं देती है।

धारा 76 संबंधित प्राधिकारी को पार्किंग स्थल निर्धारित करने में सक्षम या सशक्त बनाती है। यह इस अर्थ में वैधानिक दायित्व नहीं है कि विधानमंडल प्राधिकरण को पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने का आदेश देता है और ऐसा नहीं करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाता है। विद्वक अधिवक्ता के इस तर्क का वास्तविक प्रश्न पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा, इस मामले में 4 जून 1967 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 76 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कई स्थानों को टैक्सी स्टैंड आदि के रूप में निर्धारित किया गया था। अगला तर्क यह था कि नियम 7.12 के तहत स्टैंड की अधिसूचना जारी होने से पहले, उन याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करना अनिवार्य था जिनका मौजूदा रुख अधिसूचना में शामिल नहीं था। नियम 7.12(2) के तहत जिला मजिस्ट्रेट किसी भी स्थान को स्टैंड के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने वाला आदेश देने के लिए अधिकृत है, और "ऐसे आदेश के बिना, किसी भी स्थान का उपयोग नहीं किया जाएगा।" स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी स्थान का उपयोग स्टैंड के रूप में नहीं किया जा सकेगा जो अधिसूचना में शामिल नहीं है।

अगला तर्क जिस पर आग्रह किया गया था वह यह था कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियम 7.22 का उल्लंघन किया गया था, जहां तक कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, जो कि किसी भी स्टैंड की स्थापना की अनुमति देने वाले आदेश को रद्द करते समय उन्हें करना आवश्यक था। जिस तर्क में भ्रंति है, वह यह है कि याचिकाकर्ताओं को टैक्सी स्टैंड की स्थापना चलाने की अनुमति दी गई थी और इसके निरस्तीकरण से पहले, वे सुनवाई का अवसर

पाने के हकदार थे। याचिकाकर्ताओं को बस स्टैंड के प्रवेश द्वार के बाहर के स्थानों का उपयोग अपनी टैक्सियों को पार्क करने के लिए करने की कोई "अनुमति" कभी नहीं दी गई। "परमिट" शब्द का प्रयोग आम तौर पर दो अर्थों में किया जाता है। इसका मतलब हो सकता है कि एक देना निष्क्रिय सहमति या बस, बाधा नहीं, परमिट का उपयोग कुछ संदर्भों में "इस्तीफा देना", "पीड़ित होना", "सहन करना" और "प्रतिबंध न लगाना" के रूप में किया गया है। मुझे नहीं लगता कि नियम 7.12 (2) में प्रयुक्त "अनुमति", नियम 7.13 में "अनुमति", और नियम 7.22(1) में "अनुमति" शब्दों को उपरोक्त अर्थ में केवल आपत्ति करने में विफलता या सहमति का एक पर्याय के रूप में समझा जा सकता है। परमिट शब्द काफी लचीलेपन का शब्द है और इसका उपयोग केवल निष्क्रियता या निवारक कार्रवाई से परहेज के संकेतक के रूप में किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस शब्द का उपयोग यहां उस अर्थ में किया गया है। संदर्भ में "परमिट" को औपचारिक सहमति, अनुदान या प्राधिकरण या स्पष्ट यूसेंस देने का संकेत माना जाना चाहिए। नियम 7.7 में जिला मजिस्ट्रेटों को "अधिनियम की धारा 76 के तहत मोटर वाहनों के लिए पार्किंग स्थानों की नियुक्ति के आदेश देने के लिए" अधिकृत करने का उल्लेख है। इसका तात्पर्य स्पष्ट रूप से एक विशिष्ट आदेश बनाने से है, न कि केवल एक निष्क्रिय मौन या केवल निष्क्रियता से। नियम 7.12 (2) के तहत, जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करते समय किसी भी स्थान को एक स्टैंड के रूप में उपयोग की अनुमति देते हुए निर्धारित प्रपत्र में आदेश देने की आवश्यकता होती है।" इस पर आगे जोर दिया गया है कि "इस तरह के आदेश के बिना, किसी भी स्थान का इस तरह उपयोग नहीं किया जाएगा"। निर्धारित प्रपत्र में आदेश के अभाव में याचिकाकर्ताओं द्वारा टैक्सी स्टैंड के रूप में उस स्थान का उपयोग करना नियम द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।

इसी प्रकार, नियम 7.13 किसी भी स्थान को स्टैंड के रूप में उपयोग करने के लिए विशेष रूप से "अनुमति देना" शब्दों का उपयोग करता है। इस प्रकार, किसी स्थान को टैक्सी स्टैंड के रूप में उपयोग करने की अनुमति, जहां भी उपयोग की जाती है, एक व्यक्त या सचेत अनुमति को संदर्भित करती है, न कि केवल निष्क्रियता को। याचिकाकर्ताओं के पास कभी भी उस स्थान को टैक्सी स्टैंड के रूप में उपयोग करने की कोई अनुमति नहीं थी और किसी अधिसूचना के अभाव में किसी भी स्थान का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत स्थान को टैक्सी स्टैंड के रूप में उपयोग करने का कोई अधिकार याचिकाकर्ताओं के पास नहीं है, क्योंकि पिछले कई वर्षों के दौरान, उन्होंने बिना किसी बाधा या आपत्ति के इसका उपयोग किया है। नोटिस की सेवा या अवसर देने की आवश्यकता वाले प्रावधान इस मामले की परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वक अधिवक्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले *इब्राहीम साहब बनाम क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण(1)* पर भरोसा जताया है। एक प्रस्ताव द्वारा, तंजौर के परिवहन प्राधिकरण ने एक निश्चित निजी बस-स्टैंड को अनुपयुक्त घोषित कर दिया था और उस भूमि के पट्टेदार को नोटिस दिए बिना एक नया बस-स्टैंड तय कर दिया था, जिसे पहले बस-स्टैंड के

रूप में इस्तेमाल किया गया था। पट्टाधारक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के निर्णय से व्यथित महसूस कर रहा था। ऐसा महसूस किया गया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का संकल्प एक अर्ध-न्यायिक निकाय का था। उस मामले के जो भी अजीब तथ्य हों, जिला मजिस्ट्रेट का याचिकाकर्ताओं के तंबू हटाने या शहर में कुछ स्थानों को टैक्सी स्टैंड के रूप में अधिसूचित करने और वर्तमान स्थान को टैक्सी स्टैंड के रूप में शामिल न करने का आदेश प्रशासनिक है और कार्यकारी चरित्र का हिस्सा है। वर्तमान स्टैंड का स्थान सार्वजनिक सड़क का एक हिस्सा है और याचिकाकर्ता न तो मालिक हैं, न पट्टेदार और न ही लाइसेंसधारी, वे सिर्फ अतिक्रमणकर्ता थे; और इस प्रकार, वे उस स्थान को टैक्सी स्टैंड के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दिए जाने के विरुद्ध कारण बताने के लिए किसी नोटिस या अवसर के हकदार नहीं हैं।

"कब्जाकर्ता" वह व्यक्ति है जो बिना किसी वास्तविक दावे या स्वामित्व के रंग के और मालिक की सहमति के बिना, घेरी हुई या बिना घेरी गई भूमि पर बसता है या बसता है। ऐसा व्यक्ति महज एक घुसपैठिया है; और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वहां कितने समय तक बना रह सकता है, कानून में उसका कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं की स्थिति अलग नहीं है

मेरे विचार में, याचिका में कोई दम नहीं है और यह खारिज किये जाने योग्य है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

K.S.K.

(1) A.I.R. 1951 Mad. 419.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैं ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

रुहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा